

## प्रकृति, पर्यावरण और हिंदी उपन्यास

रवि यादव

शोध छात्र, हिंदी विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

### ARTICLE DETAILS

#### Article History

Published Online: 16 Mar 2020

#### Keywords

प्रकृति, पर्यावरण, भूमंडलीकरण, हिंदी उपन्यास

#### \*Corresponding Author

Email: ravijasrana[at]gmail.com

### ABSTRACT

21वीं सदी का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है. भूमंडलीकरण के बाद अर्थव्यवस्थाओं की आपस में निर्भरता ने एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल दिए. ऐसे में आर्थिक विकास की अंधी दौड़ शुरू हो गई है. ऐसे की इस भूख ने विलासिता को जन्म दिया है. मानव का यह विलासिता पूर्ण जीवन प्राकृतिक संसाधनों को तेजी खत्म कर रहा है. तेजी से बढ़ता जनसंख्या दबाव ने संसाधनों के दोहन की इस गति को और तीव्र कर दिया है. मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अगर सबसे अधिक किसी ने कीमत चुकाई है तो वह है हमारा पर्यावरण, हमारे आस पास का वातावरण, प्रकृति और उसपर निर्भर जीव जन्तुओं और प्राणियों ने. एक तरफ महानगरों में निवास करने वाले लोग पर्यावरण प्रदूषण की मार झेल रहे हैं तो दूसरी ओर प्रकृति की गोद में रह रहा आदिवासी समुदाय औद्योगिक कंपनियों की नव उपनिवेशवादी मॉडल की जद में आकर अपनी निजी भूमि पर पराया होता जा जा रहा है. पर्यावरण निम्नीकरण की इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जारी है. साहित्यिक कृतियों के माध्यम से भी रचनाकारों ने वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करने और सुधार के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है

आज इन्सान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और आधुनिकीकरण के समक्ष सामंजस्य बैठना है. जिस तेजी से जंगलों की कटाई और पर्यावरण को कुचल कर हम तेजी से आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं ऐसे में हम पारिस्थिकी तंत्र को छति पहुंचा रहे हैं. जीवन चक्र को सुरक्षित रखने के लिये पर्यावरण को संतुलित एवं सुरक्षित रखना वेहद जरूरी है. हल ही में सरकार ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन के लिए कई प्रभावी कदम उठाये हैं. बात उर्जा की हो, पर्यावरण और जीव जन्तुओं के संरक्षण की हो या जल संरक्षण की हो सरकार ने तेजी से और प्रतिवद्धता के साथ इस दिशा में कदम उठाये हैं. प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी चैनल के एक कार्यक्रम 'मेन बर्सस वाइल्ड' में हिस्सेदारी करना आम समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदना पैदा करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है. इस कार्यक्रम में वे पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जंगलों में जाने का जोखिम उठाते हुए दिखे. संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण को लेकर चलाये जाने वाले कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा 'चैंपियन ऑफ

द अर्थ' अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया गया. भारत के इन प्रयासों ने भारत को पर्यावरण संरक्षण में फ्रंट रनर बनाये रखा है. भारत यू.एन. द्वारा कार्बन उत्सर्जन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर चुका है साथ ही भारत वाघों के लिए लिए सबसे सुरक्षित और बड़े पर्यावास के रूप में उभर कर सामने आया है. दुनिया के तीन चौथाई बाघ भारत में हैं.

इन सब के बावजूद आज देश कई प्रकार की पर्यावरण के प्रति समस्याओं से जूझ रहा है. तेजी से बदलती जनसंख्या के कारण नए शहरों का तेजी से विकास हो रहा है. बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण भारत की उर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं. अतः इसके लिए उत्पादन बढ़ाना ही एक मात्र विकल्प है. लेकिन इस उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा की इसके दुसपरिणाम क्या हैं. वर्तमान समय में भारत का उर्जा उत्पादन सर्वाधिक खनिज ईंधन आधारित है ऐसे में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन इसी क्षेत्र से होता है. अतः बढ़ती उर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए हमें उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना होगा. हालांकि इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है. सरकार सौर उर्जा

बढ़ाने की क्षमता के विस्तार में लगातार लगी हुयी है.भारत की घनी अवादी और उच्च सौर विकरण इसको सौर उर्जा के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करता है .लेकिन उर्जा उत्पादन में आने वाले अत्यधिक खर्च की वजह से ये क्षेत्र उपेक्षित चल रहा है .लेकिन हल ही में सौर उर्जा के क्षेत्र में किये गए प्रयास तथा २०२२ तक 1 लाख मेगावाट उर्जा उत्पादन का लक्ष्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है .झारखंड जोकि सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है में देश के प्रधानमंत्री द्वारा २०१५ में सौर उर्जा चालित कोर्ट का उद्घाटन सांकेतिक ही सही लेकिन नवीकरणीय उर्जा उत्पादन की दिशा में बल देने और लोगो में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.इन छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से ही हम बड़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपट सकते हैं.

आज जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से निपटने का हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें प्राचीन दर्शन और शास्त्रों की तरफ भी देखना होगा.भारत में सूर्य को पूरे जीवन का पोषक मन गया है.हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही पर्यावरण चेतना और संरक्षण की बात की गयी है. वैदिक ग्रंथो और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में पेड़ काटना निषेध घोषित किया गया है .बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में भी पर्यावरण से संबन्धित बहुत उपदेश को दिया गया हैं। विनय पिटक, जिसे बौद्ध धर्म की 'आचार संहिता' कहा जाता है, में वातावरण को संतुलित बने रहने के उद्देश्य से पेड़ काटने से विरत का उपदेश दिया गया।कोई भिक्षु अगर किसी तरह की पेड़ काटता है तो उसे पाराजिक नामक अपराध में रखा जाता है-

"महग्धरुक्खे छिन्नमत्ते पाराजिकं।

1985 में भारत ने नीतिगत प्रक्रिया के तहत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पहलुओं को शामिल कर लिया था. वन संरक्षण के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर ध्यान दिया गया था .सार्वजनिक निजी भागीदारी तहत पौधों को लगाना तथा पार्कों का निर्माण जैसे प्रयासों को प्रमुखता दी गयी .उपग्रहों की तैनाती ,एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लैब,गहरे घने जंगलो की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती,कैमरे आदि .के उपयोग से पर्यावरण प्रबंधन में प्रोद्योगिकी का प्रोयाग द्वारा सटीक जानकारी हासिल करने में सफलता मिली है .

प्लास्टिक प्रदूषको पर प्रतिबंध,एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध,घरेलू ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से एल.पी.जी.सिलेंडरो की आपूर्ति,अपशिष्ट और वायोमेडीकल बेस्ट के प्रबंधन के लिए नीति ,चिंतन शिविर,स्कूल नर्सरी कार्यक्रम ,जलवायु परिवर्तन विशेष एक्सप्रेस जैसी पहले प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार के प्रयास सराहनीय है इस दिशा में हमें विकास को पर्यावरण का विरोधी मानने वाली अवधारणा से उवरते हुए सकारात्मक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है.

भारत राज्य बन रिपोर्ट के अनुसार कुल बन क्षेत्र में 3775 वर्ग किलो मीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है .यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है वही दूसरी ओर मेघालय,त्रपुरा,अरुणाचल और मध्य प्रदेश जैसे सघन बन वाले राज्यों के वन आवरण में कमी दर्ज किया जाना निराशापूर्ण हैं.भारत में कुल जंगल वृक्ष आवरण 79.42 मिली हेक्टर है जोकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16 प्रतिशत है.(भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019)संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए.ऐसे में भारत इस आंकड़े में पिछड़ जाता है अतः वृक्षारोपण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयसो की आवश्यकता है .जब तक व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास नहीं किये जाते केवल सरकारों के प्रयासों से इन लक्ष्यों हासिल नहीं किया जा सकता .

चूकि साहित्य समाज का दर्पण है अतः पर्यावरण की इन समस्याओ को लेकर साहित्य भी अछूता नहीं रह सकता .प्राग्भिक दौर में जहाँ हिंदी कविता प्रकृति की सौंदर्य का बखान कर रही थी, प्रकृति के सौन्दर्य में जीवन का सौन्दर्य दूडने का प्रयास कर रही थी. सन 1990के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन और बाजार की पहुच जंगलो और अदिवासियों तक हुई बैसे ही हिंदी साहित्य में प्राकृतिक सौंदर्य से इतर भी लेखन शुरु हुआ. अब यहाँ सौंदर्य के साथ पर्यावरण और स्थानीय निवासियों की समस्याए भी थी .तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण और जनसँख्या दबाव और संशाधनो की पूर्ती के लिए होने वाले खनन ने जंगलो को काटना शुरु कर दिया.जिससे स्थानीय लोगो को समस्याए होने लगी.इन समस्याओ को लेकर पिछले दो दशको में कई उपन्यास हमारे सामने आये. जिनमे उपन्यासों की बात करे तो कठगुलाब (1996)मृदुला गर्ग ,एक ब्रेक के बाद (2008)अलका सरावगी

,रह गयी दिशाए इसी पार(2011) संजीव ,मरंग गोडा नीलकंठ हुआ (2012) महुआ मांझी,ग्लोबल गाँव का देवता (2009) रणेंद्र,गायब होता देश(2014) रणेंद्र आदि प्रमुख हैं.

इन उपन्यासों में पारिस्थितिकी संकट और स्थानीय लोगो की समस्याओ को लेकर, भूमंडलीकरण के बाद उत्पन्न हुयी समस्याओ का आदिवासी जीवन पर प्रभाव,खनन से उत्पन्न हुए विकरण के खतरे ,ग्लोबल वार्मिंग की समस्या,विस्थापन ,वन अधिकारों का उल्लघन ,भूमि अधिग्रहण तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा शोषण जैसी समस्याओ पर केन्द्रित है.ये उपन्यास जंगलो में रहने वाले लोगो की जीवन संस्कृति और पर्यावरण की समस्याओ से रूबरू कराते हैं.वर्तमान राजनीतिक व्यस्था में अर्थव्यस्था का काफी महत्व है. आर्थिक प्रगति के नाम पर तेजी से जंगलो में घुसती बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अत्यंत तवाही पैदा की है.यह तवाही अब विध्वंश बन गयी है.जिसका प्रतिउत्तर विकाश परियोजनाओ का विरोध, हिंशक प्रदर्शन और नक्सलबाद के रूप में देखने को मिलता है.झारखण्ड ,छत्तीसगढ,उडीसा में खानन कंपनियों द्वारा मूल निवासियों के साथ व्यवहार और उनका विरोध इसके उदाहरण है. 'ग्लोबल गाँव का देवता' उपन्यास में रणेंद्र ने विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरे नवउपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की सर्वभक्षी भूख को चित्रित करता है.यह उपन्यास तथाकथित समाज का विकास संबधी मॉडल को नकारता है.रणेंद्र की यह रचना झारखण्ड राज्य के असुर आदिवासी समाज की भयावह व्यथा को व्यक्त करते हुए आन्तरिक उपनिवेशवाद की ओर हमारा ध्यान खीचाती है .उपन्यास झारखण्ड के साथ साथ अन्य राज्यों के दिवासी समुदायों की व्यथा को भी बखूबी व्यक्त करता है. रणेंद्र केरल की सी.के.जानू , महाराष्ट्र के कोंकण की सुरेख दलवी आदि की चर्चा करते हुए विमर्श के इस भूगोल को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और सत्ता के खूनी खेल की असलियत को उजागर करते हैं .रणेंद्र लिखते हैं कि, "सामान्य तौर पर आकाशचारी देवताओ को जब अपने आकाश मार्ग से या सेटेलईट की आँखों से छत्तीसगढ,उडीसा,मध्यप्रदेश,झारखण्ड आदि राज्यों की खनिज सम्पदा ,जंगल और अन्य संसाधन दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे,इन पर तो हमारा हक है.उन्हें मालूम है की राष्ट्र राज्य तो वे ही हैं,तो हक तो उनका ही हुआ .सो इन खनिजो पर ,जंगलो में, घूमते हुए लंगोट पहने असुर - बिरिजिया ,उराँव-मुंडा

आदिवासी ,दलित सदन दिखते हैं तो उन्हें बहुत कोफ्त होती है ' ' .(रणेंद्र,ग्लोबल गाँव का देवता) इस तरह से रणेंद्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार किये जा रहे नवउपनिवेशवाद के मॉडल और पर्यावरण निम्नीकरण के प्रयासों की तीव्र आलोचना करते हैं .

वही दूसरी ओर यूरेनियम विकिरण की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास मरंग गोडा नीलकंठ हुआ (महुआ मांझी) एक संभावित समस्या को व्यक्त करता है .यह उपन्यास महुआ मांझी के एक पत्रकार के रूप में चार वर्ष के शोध का परिणाम है.यह रचना उन्होंने समाजशास्त्री ,मानव शास्त्री और पर्यावरण शोधकर्ता के रूप में लिखी है.जो झारखंड की यूरेनियम खदानों से निकलने वाले विकिरण और उनमें रहने वाले स्थानीय लोगो के विस्थापन को व्यक्त करती है.मांझी लिखती है , "परमाणु सयंत्रों में एक हजार मेगावाट विजली पैदा करने से करीब 27 किलो ग्राम रेडिओधर्मी कचरा पैदा होता है और उसे निष्क्रिय होने में हजार साल से भी अधिक समय लग सकता है यह एक विडम्बना ही है की अधिकतर यूरेनियम खदाने ,परमाणु रिएक्टर या परमाणु कचरा फेके जाने वाले टेलिंग डैम आदिवासी इलाकों में ही होते हैं."आदिवासियों की समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है पूरी दुनिया में देखा जाये तो आदिवासी किसी न किसी रूप में पीड़ित या शोषित किये जा रहे हैं. महुआ मांझी का उपन्यास 'मरंग गोडा नीलकंठ हुआ' वस्तुतः जमशेदपुर से 30 किलो मीटर दूर स्थित जदूगोडा नमक वह कस्बा है जहाँ 1967 में शुरु हुए यूरेनियम खनन से आस पास में 15 गांवों के लोग विकिरण से प्रभावित हुए .लेखिका कहती है कि जो जमीन यूरेनियम को पीकर नीलकंठ हुई वही दुनिया भर को रोशानी प्रदान करती है.

हिंदी साहित्य में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओ ,प्रकृति के सौन्दर्य चित्रण व मानवीकरण से लेकर पर्यावरण प्रदूषण ,भूमंडलीकरण व अन्य महत्वपूर्ण समस्याओ पर मंथन किया गया है .चिंतन करने के साथ ही साथ उन समस्याओ का तार्किक व उपयुक्त समाधान भी प्रस्तुत किया गया है .साहित्य मानव को प्राकृत से तालमेल बैठाने के सुझावों और संशाधनो के उचित उपयोग की बात करता है .मानव का सम्पूर्ण अस्तित्व पृथ्वी से ही जुडा हुआ है .वह आपने जीवन की सभी आवश्यकताओ की पूर्ती के लिए प्रकृति पर पूर्णतःनिर्भर है अतः उसे नष्ट कर वह स्वयं भी सुरक्षित नहीं

रह सकता है . मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचने के लिए सतत रूप से संसाधनों के उपयोग के विषय में सोचना अनिवार्य है .पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तब तक कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता जब तक व्यक्तिगत रूप से प्रयास नहीं किये जायेगे, सिर्फ सरकारों के या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है .बढ़ता जनसँख्या दबाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे हानिकारक पहलू है .बढ़ती जनसँख्या न सिर्फ संसाधनों पर दबाव बनती है बल्कि एक अविवस्था भी पैदा करती है जो सामाजिक रूप से विध्वंस

का कारण बनती है. अतः हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले जनसँख्या नियंत्रण की भी बात करनी होगी. सरकारों को इस दिशा में सख्त कानूनों के माध्यम से पर्यावरण विषयक नीतियों को लागू करने तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति संवेदना पैदा करने की दिशा में जागरूकता कार्यक्रमों के चलाये जाने की आवश्यकता है .इन सभी मिले जुले प्रयत्नों के मध्यम से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है .

### सन्दर्भ सूची

1. भारत वन रिपोर्ट 2019,जलवायु एवं वन मंत्रालय ,भारत सरकार
2. रणेंद्र,2009,ग्लोबल गाँव का देवता ,ज्ञानपीठ प्रकाशन,दिल्ली
3. मांझी महुआ ,2012,मरंग गोडा नीलकंठ हुआ ,राजकमल प्रकाशन,दिल्ली
4. चातक गोविन्द,2000,पर्यावरण परम्परा और अपसंस्कृति,तेज प्रकाशन ,नई दिल्ली